PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 057
दि. 26.06.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

'कभी माफ न करें, कभी न भूलें' आपातकाल की 51वीं बरसी पर बोले प्रधानमंत्री मोदी

1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल की 51वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने नागरिकों से कहा कि इस दाग को बार-बार याद करने की जरूरत है, ताकि देश में फिर कोई ऐसा पैदा न हो, जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए।

नई दिल्ली, 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल की 51वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने नागरिकों से कहा कि इस दाग को बार-बार याद करने की जरूरत है, ताकि देश में फिर कोई ऐसा पैदा न हो, जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर हैशटैग 'संविधान हत्या दिवस' के साथ पोस्ट किया, "क्या आप जानते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून इतना महत्वपूर्ण क्यों है?"

उन्होंने लिखा, "आपातकाल लगाने वालों के माथे पर उस गंभीर पाप का कलंक हमेशा के लिए लग गया है। आज हम उन सभी लोगों को सलाम करते हैं, जो डटकर खड़े रहे। उन्हीं की वजह से लोकतंत्र बचा रहा। कभी माफ न करें और कभी न भूलें।"

पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में शुरूआत में इंदिरा गांधी के आपातकाल की घोषणा का अंश शेयर किया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री को कहते सुना गया, "राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।" प्रधानमंत्री ने इसका शीर्षक दिया, "आपातकाल की 51वीं बरसी- जानिए क्यों इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है।"

पीएम मोदी ने संदेश में कहा, "आपातकाल लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया। इसके अनेक उदाहरण हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं

जा सकता है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था और अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गईं। मीसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। छात्रों को भी परेशान किया गया। अभिव्यक्ति की आजादी का भी गला घोंट दिया गया था। साथियों, उस दौर में जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार हुए।"

उन्होंने कहा, "देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेलखाना बना दिया गया था, और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए, इसलिए।"

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, "आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को यातनाएं दी गईं। उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था। जिस संसद के अंदर होता था, वह तो रिकॉर्ड पर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह दौर कैसा था। आपातकाल लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था, लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं।"

इस दौरान, पीएम मोदी ने कहा कि जनभागीदारी की शक्ति से बड़े-बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। उस समय जब मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर किसी को लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी और पकड़ लेगी। ऐसे वातावरण में मेरे देश के लोगों का सामर्थ और ताकत देखिए, जाति, पंथ व संप्रदाय, इन सबसे ऊपर उठकर देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था, लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुनःस्थापित किया था। ये मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है।

अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने का पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये पाप कभी मिटने वाला नहीं है। इस दाग को बार-बार स्मरण करने की भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कोई ऐसा पैदा न हो, जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला-बुरा कहने के लिए नहीं।"

यूपी बनेगा 'समृद्ध भारत' का इंजन, लखनऊ में खुलेगा क्लीन प्लांट सेंटर; सीएम योगी और शिवराज सिंह चौहान ने तैयार किया नया कृषि रोडमैप

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बागवानी और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने एक मजबूत 'कृषि रोडमैप' तैयार किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में 'क्लीन प्लांट सेंटर' (उ'ॅल्ल ढ'ल्ल३ उील्ल३ी१) स्थापित करने का बड़ा ऐलान किया है। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोगमुक्त पौधे उपलब्ध कराना है, जिससे प्रदेश में बागवानी का दायरा बढ़ेगा और किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा।

गुरुवार को लखनऊ स्थित योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं की संयुक्त समीक्षा बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि 'विकसित भारत' का सपना बिना 'समृद्ध उत्तर प्रदेश' के पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कभी 'बीमारू' कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश ने पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आज यूपी जिस गति से ग्रामीण और कृषि विकास की ओर बढ़ रहा है, वह पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है।

बैठक में किसानों के हित में दो बड़े फैसले लिए गए। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ा दी गई है, जिसका आशय पत्र केंद्रीय मंत्री ने सीएम योगी को सौंपा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने का अधिक अवसर मिलेगा। दूसरा बड़ा ऐलान ग्रामीण विकास को लेकर हुआ, जहाँ 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' के आगामी चरण के लिए 6,18,482 पात्र लाभार्थियों की सूची यूपी सरकार को सौंपी गई। सीएम योगी ने पारदर्शी तरीके से हर पात्र को घर देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक का एक अहम हिस्सा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का प्रस्तुतीकरण रहा। ICAR के महानिदेशक ने बताया कि वर्तमान में यूपी की कृषि अर्थव्यवस्था 7.41 ट्रिलियन रुपये की है। लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक इसे 96.96 ट्रिलियन रुपये तक पहुँचाया जाए। इसके लिए कृषि वृद्धि दर को 3.19% से बढ़ाकर 5.41% करना होगा। रोडमैप में धान और गेहूं पर निर्भरता कम कर दलहन, तिलहन, मोटे अनाज और मक्का की खेती पर जोर देने (कृषि विविधीकरण) की सलाह दी गई।

तकनीक, सिंचाई और सॉयल हेल्थ कार्ड पर जोर

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 'सॉयल हेल्थ कार्ड' (रङ्क' ल्ीं'इँ उं१ि) केवल कागज तक सीमित न रहे, बल्कि किसानों को मिट्टी की असल स्थिति और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए।

शादी के कार्ड पर छपवानी होगी दूल्हा-दुल्हन की जन्मतिथि

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार राज्य सरकार एक नया और कड़ा प्रशासनिक कदम उठाने जा रही है। जिसके तहत अब राज्य में शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्मतिथि अनिवार्य रूप से छपवानी पड़ेगी। अगर नियम का पालन नहीं

किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। इतना ही नहीं प्रिंटिंग प्रेस और मैरिज हॉल की भी इस मामले में कानूनी जवाबदेही होगी। महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक कुरीति पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए ये नया और अनोखा नियम लागू करने की योजना बना रही है।

कोलकाता हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान

(जीएनएस)।

कोलकाता के तारातला इलाके में हुए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, पीएम मोदी ने मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बुधवार को कोलकाता में हुई दुर्घटना दुखद है। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मिले।

ज्ञात हो, कोलकाता के तारातला इलाके में कल बुधवार को निमार्णाधीन गोदाम की छत गिरने से अब तक कई

लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के 20 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।

घटनास्थल पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की दूसरी बटालियन के कमांडेंट मनीष रंजन ने न्यूज एजेंसी से बताया कि अब तक काफी लोगों को सुरक्षित जीवित बाहर निकाला जा चुका है।

मनीष रंजन ने कहा कि बचाव अभियान काफी कठिन है, क्योंकि ढही हुई संरचना में कंक्रीट की कई परतें, लोहे की सरिए, गर्डर और टिन की चादरें शामिल हैं। इससे मलबे के अंदर पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है।

पुलिस ने इस मामले में गोदाम के मालिक शंभूनाथ बहरा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही, इस हादसे से जुड़े मामले में अब तक कुल तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

धामी सरकार ने पहली 'महिला नीति' लाकर रचा इतिहास, अब गांव से नौकरी तक दिखेंगी महिलाएं

(जीएनएस)।

उत्तराखंड ने महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने पहली बार एक समर्पित महिला नीति को मंजूरी दी है, जिसका मकसद महिलाओं की भागीदारी को सिर्फ कल्याण योजनाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें रोजगार, नेतृत्व, कारोबार और स्थानीय शासन के केंद्र में लाना है। यह नीति ऐसे समय आई है जब देशभर में महिला-नेतृत्व वाले विकास मॉडल पर चर्चा तेज हो रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंबे समय से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने वाली योजनाओं पर जोर देते रहे हैं। इस नई नीति के जरिए सरकार का इरादा साफ है कि महिलाओं को सिर्फ घर-गृहस्थी या खेतों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि नौकरी, व्यापार और गांव के बड़े फैसलों में उनकी सीधी हिस्सेदारी तय हो।

सीएम धामी का कहना है, "महिलाएं उत्तराखंड के समाज की रीढ़ हैं। हमारी सरकार का मानना है कि महिलाओं को सशक्त बनाए बिना समाज की प्रगति संभव नहीं है। यही वजह है कि हमने महिलाओं के लिए कई विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होंगी। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए हम जल्द ही एक व्यापक महिला नीति लेकर आ रहे हैं।"

सीएम धामी अपने कार्यकल में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले ले चुके हैं। इनमें सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण और पहली बार सहकारी समितियों में महिलाओं को आरक्षण देने जैसे कदम शामिल हैं। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिला सारथी योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं को भी जमीन पर उतारा गया है।

गांव की सरकार में महिलाओं की सीधी एंट्री, बनेंगी महिला सभाएं

इस नीति का सबसे बेहतरीन हिस्सा जमीनी स्तर पर महिलाओं को ताकत देना है। अब तक गांवों के विकास और बजट की प्लानिंग में महिलाओं की बातें अक्सर अनसुनी रह जाती थीं। लेकिन अब इस समस्या का परमानेंट इलाज कर दिया गया है।

नई नीति के तहत अब ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष 'महिला सभाओं' का गठन किया जाएगा। ये सभाएं सीधे स्थानीय शासन और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में अपनी राय रखेंगी। इससे गांव की महिलाओं की आवाज सीधे प्रशासनिक प्लानिंग का हिस्सा बनेगी। जब गांव के विकास का खाका तैयार होगा, तो उसमें महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिलना तय हो जाएगा।

दिल्ली की सड़कों पर खर्च होंगे ₹658 करोड़! रेखा सरकार का मेगा प्लान, 270 किमी रोड नेटवर्क की बदलेगी तस्वीर

(जीएनएस)।

दिल्ली की टूटी सड़कों, गड्ढों और बार-बार होने वाली मरम्मत की शिकायतों के बीच राजधानी सरकार ने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान मंजूर किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति (एऋ) की बैठक में 270 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 658 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई।

सरकार का दावा है कि यह केवल सड़क मरम्मत का काम नहीं होगा, बल्कि राजधानी के प्रमुख मार्गों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने की कोशिश है। बैठक में लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

इस परियोजना के तहत दिल्ली को तीन जोन में बांटा गया है। पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली की प्रमुख सड़कों को

नए सिरे से मजबूत किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली में 58.29 किलोमीटर सड़क नेटवर्क पर काम होगा, जिसके लिए 147.08 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

उत्तरी दिल्ली में 104.42 किलोमीटर सड़कों के लिए 247.31 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली में सबसे बड़ा काम होगा, जहां 107.92 किलोमीटर सड़कें 263.61 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ की जाएंगी। सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

लोक निर्माण विभाग इस बार सड़क निर्माण में नई तकनीक का इस्तेमाल करेगा। पहले पुरानी और क्षतिग्रस्त सड़क की ऊपरी परत को मशीनों से हटाया जाएगा। इसके बाद नई और अधिक मजबूत सतह बिछाई जाएगी, जिससे सड़क की उम्र बढ़े और बार-बार मरम्मत की जरूरत कम पड़े। इसके साथ सड़कों पर नई लेन मार्किंग, आधुनिक साइन बोर्ड और बेहतर जल निकासी व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। इसका मकसद सिर्फ सड़क बनाना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना भी है।

इस परियोजना की एक और खास बात टेंडर प्रक्रिया में किया गया बदलाव है। अब हर सड़क के लिए अलग-अलग टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे।

राम मंदिर घोटाले में 8 के खिलाफ एफआईआर, टिन्नू यादव समेत लिस्ट में कौन-कौन? और भी नाम हो सकते हैं शामिल

(जीएनएस)।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन का मामला अब कानूनी रूप ले चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर राम जन्मभूमि कोतवाली में 8 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने SIT की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह शिकायत दर्ज कराई। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव (रामशंकर यादव) इस मामले में सबसे चर्चित नाम है।

FIR में चंपत राय समेत उच्च पदाधिकारियों के नाम नहीं हैं, जिससे राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह प्रकरण लाखों भक्तों की आस्था, ट्रस्ट की पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है।

मुख्य आरोपी कौन-कौन? FIR में पूरी लिस्ट

SIT की जांच और शिकायत के आधार पर मुख्य नाम इस प्रकार हैं:

1. टिन्नू यादव (राम शंकर यादव): सबसे चर्चित नाम। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी माने जाते हैं। पूर्व में ऑटो ड्राइवर रहे, बाद में चढ़ावा प्रबंधन और दर्शन व्यवस्था से जुड़े। 2. लवकुश मिश्रा 3. अनुकल्प मिश्रा 4. अविनाश शुक्ला 5. मनीष यादव 6. रामाशंकर मिश्रा 7. सुभाष चंद्र श्रीवास्तव 8. करुणेश पांडेय

SIT रिपोर्ट में और 2-3 नाम शामिल बताए जा रहे हैं, जांच आगे बढ़ने पर अतिरिक्त नाम सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर SIT ने 17 लोगों को संदिग्ध माना था, जिनमें उच्च पदाधिकारी भी शामिल थे।

टिन्नू यादव मुख्य आरोपी क्यों?

टिन्नू यादव पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। जांच के दौरान उनके पास दानपात्रों की चाबियां मिलने की खबरें आईं। उनके घर से करोड़ों रुपये मूल्य के सोने-नकदी की बरामदगी और अचानक बढ़ी संपत्ति के आरोप लगे हैं। टिन्नू ने इन आरोपों से इनकार किया है और अपनी संपत्ति को पुरानी बता कर सफाई दी है।

सम्पादकीय

होने वाले हैं यूएस-भारत ट्रेड डील पर हस्ताक्षर

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता अपने अन्तिम चरण में पहुंच गया है किन्तु वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा यह शर्त रखे जाने कि जब तक भारतीय निर्यातकों को दूसरे प्रतिस्पधी देशों के मुकाबले तुलनात्मक टैरिफ लाभ देने वाला ढांचा तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। यह इस बात का परिचायक है कि दोनों पक्ष अभी भी अपने-अपने लक्ष्यों को लेकर अड़े हुए हैं। यद्यापि यह बात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ही कही कि इस वर्ष की शुरूआत में 6 फरवरी को दोनों देशों के बीच समझौते में शामिल बिन्दुओं पर सहमति बन गईं थी किन्तु उसके बाद दोनों देशों के वाणिज्य विभाग की टीमें लगातार समझौते के प्रावधानों की बारीकियों पर बातचीत कर रही हैं। जिस तरह अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अधिकारी अपने व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों की चिन्ता कर रहे हैं, ठीक उसी तरह भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की टीम भारतीय व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों के लिए चिन्तित हैं। दोनों देश अपने-अपने हितों के टकराव को टालने के लिए बारीकी से प्रस्ताव के प्रारूप की समीक्षा कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है किन्तु यदि दबाव डालकर ट्रेड डील के प्रारूप पर अमेरिका ने प्रयास किया तो निश्चित रूप से भारत ट्रेड डील को मानने से इंकार कर देगा।

सच तो यह है कि कोई भी समझौता तभी संपन्न होता है जब दोनों पक्ष वुछ छोड़ने के लिए तैयार रहे। समझौते का तो स्थाई भाव ही 'समर्पण' है। अकड़ से कोई समझौता संपन्न हो ही नहीं सकता। यह भी सच है कि अकड़ में हमेशा वह देश रहता है जिसके पक्ष में व्यापार संतुलन का तराजू झुका होता है। मतलब जिस देश का निर्यात ज्यादा और आयात कम होता है। उसको लगता है कि उसके देश के उपभोक्ताओं को दूसरे पक्ष के उत्पाद की जरूरत ज्यादा नहीं है। लेकिन भारत के साथ अमेरिका अपनी अकड़ नहीं दिखा सकता। कारण कि भारत की जनसंख्या में मध्यम वर्ग की आबादी 31 प्रतिशत से 43 प्रतिशत तक है जबकि उच्च आय और उच्च मध्यम वर्ग में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग आते हैं। मतलब कि 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच भारत में संपन्न वर्ग के लोग रहते हैं। अमेरिकी नीति निर्धारकों को हमेशा इस बात की गलतफहमी रहती है कि भारत में उपभोक्ताओं के पास व्रय शक्ति का अभाव है। इसी अज्ञानता के वशीभूत अमेरिकी अधिकारी यह नहीं समझ पाते कि भारत में जितने मध्यम वर्ग के लोग हैं, उससे कम तो यूरोप के कई देशों की वुल आबादी है। बहरहाल ट्रेड डील होने में भले ही विलम्ब हो, किन्तु संदेह का निराकरण होना आवश्यक होता है। समझौते का स्थायित्व ही आपसी समझ पर निर्भर होता है। भारत की शर्त ऐसी नहीं है जिसे पूरा न किया जा सके। इसीलिए भारत समझौते के लिए समझौता नहीं करना चाहता बल्कि अपने व्यापारियों के लिए टैरिफ लाभ चाहता है जो कि आवश्यक भी है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए जो भी देश घाटे का सौदा करेगा, उस देश की सरकार को विपक्ष की आलोचना का पात्र और जनता का कोपभाजन बनना पड़ेगा।

इसलिए समझौते के प्रारूप की बारीकियों का अध्ययन करके ही भारत और अमेरिका समझौते पर हस्ताक्षर करें तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा।

बेंगलुरु रोड शो में चमका यूपी मॉडल! योगी सरकार की नीतियों के मुरीद हुए ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स, बोले- भारत की अगली ग्रोथ स्टोरी लिखेगा यूपी

(जीएनएस)।

बेंगलुरु में आयोजित 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग-2026' रोड शो में देश-विदेश की दिग्गज कंपनियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की जमकर तारीफ की है. एम्बेसी ग्रुप, आईबीएम और कॉग्निजेंट जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और शानदार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते यूपी निवेश की सबसे पसंदीदा जगह बन चुका है. कार्यक्रम के दौरान आईबीएम (IBM) ने लखनऊ में नई सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करने और कॉग्निजेंट ने नोएडा में अपने बड़े विस्तार की जानकारी साझा की.

गौरतलब है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग-2026 के इंडस्ट्री लीडर्स रोड शो में देश-विदेश की बड़ी कंपनियों के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास के लिए उभरता हुआ राज्य बताया है. कार्यक्रम के दौरान एम्बेसी ग्रुप, आईबीएम और कॉग्निजेंट के वरिष्ठ अधिकारियों ने योगी सरकार की नीतियों की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सुशासन के क्षेत्र में तेज प्रगति की है. बेहतर कानून-व्यवस्था, मजबूत कनेक्टिविटी और उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण आज उत्तर प्रदेश देश-विदेश के निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है.

एम्बेसी ग्रुप के सीईओ अमित शेट्टी ने उत्तर प्रदेश को भारत की सबसे महत्वपूर्ण विकास गाथाओं में से एक बताया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल एक बड़ा राज्य नहीं, बल्कि व्यापकता, महत्वाकांक्षा, प्रतिभा, उद्यमशीलता और नए भारत की उभरती आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे भारत आर्थिक विस्तार के अगले चरण में आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि निवेश कहां आएगा, रोजगार कहां सृजित होंगे और भविष्य के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहां विकसित होंगे.

अमित शेट्टी ने कहा कि भारत की विकास गाथा अब केवल कुछ महानगरों तक सीमित नहीं है. यह नए कॉरिडोर, नए शहरों और नए उद्यम केंद्रों तक विस्तार कर रही है. ऐसे में उत्तर प्रदेश निवेश की अगली बड़ी मंजिल बनकर उभर रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ तेजी से निवेश के प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहे हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहले ही एनसीआर के भीतर महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी और बिजनेस हब बन चुके हैं. मजबूत एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी, दिल्ली की निकटता और जेवर एयरपोर्ट इस क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बना रहे हैं.

अमित शेट्टी ने लखनऊ को लेकर कहा कि यह शहर अब केवल अपनी संस्कृति और प्रशासनिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आधुनिक शहरी आर्थिक केंद्र के रूप में तेजी से

विकसित हो रहा है. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, संगठित रिटेल, बढ़ती सर्विस इकोनॉमी और मजबूत टैलेंट बेस ने लखनऊ को नई पहचान दी है.

आईबीएम इंडिया और साउथ एशिया की सीएफओ तेजस्विनी राजवाड़े ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में व्यावसायिक माहौल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य निवेशकों के लिए बेहद भरोसेमंद गंतव्य बन गया है. तेजस्विनी राजवाड़े ने कहा कि निवेश मित्र, सेक्टर-विशिष्ट नीतियां और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति योगी सरकार की प्रतिबद्धता ने यह साबित किया है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक स्तर का निवेश इकोसिस्टम तैयार करने के लिए पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क और कनेक्टिविटी में किए गए निवेश भविष्य के उद्योगों के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं.

तेजस्विनी राजवाड़े ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत इसकी युवा आबादी और प्रतिभाशाली मानव संसाधन है. राज्य में युवाओं, इंजीनियरों और स्नातकों की विशाल संख्या इसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का अग्रणी केंद्र बनने की क्षमता देती है. तेजस्विनी ने कहा कि आईबीएम के लिए सबसे उत्साहजनक बात यह है कि उत्तर प्रदेश केवल तकनीक को अपनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नई तकनीकों को आकार देने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सुरक्षा, विकास और सुशासन पर दिया गया जोर निवेशकों के बीच भरोसे और विश्वास की मजबूत नींव बना रहा है.

तेजस्विनी राजवाड़े ने बताया कि इस वर्ष की शुरूआत में आईबीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में लखनऊ में एआई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया. इस पहल को आगे बढ़ाते हुए आईबीएम ने लखनऊ में एक नई सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करने की घोषणा भी की है. यह लैब जनरेटिव एआई और ऑथेंटिक एआई तकनीकों पर केंद्रित होगी. उन्होंने कहा कि यह सुविधा आईबीएम के वैश्विक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इकोसिस्टम का हिस्सा बनेगी और अगली पीढ़ी के एआई समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

कॉग्निजेंट के वाइस प्रेसिडेंट गौरव हाजरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश और एनसीआर क्षेत्र आज प्रतिभा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस ऑपरेशंस के लिए तेजी से प्रतिस्पर्धी केंद्र बन रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में कॉग्निजेंट ने 2015 में अपने संचालन की शुरूआत की थी. आज केवल नोएडा में कंपनी के 10,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी लगभग 10,000 कर्मचारी हैं. गौरव हाजरा ने कहा कि योगी सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियां निवेशकों के लिए बेहद सकारात्मक संकेत दे रही हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, सिंगल विंडो सिस्टम और निवेश मित्र जैसे प्लेटफॉर्म ने निवेश प्रक्रिया को काफी सरल बनाया है.

गौरव हाजरा ने जीसीसी नीति की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि 25 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सपोर्ट और बड़े निवेशकों के लिए लचीली संरचना जैसी नीतियां उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए बेहद आकर्षक बनाती हैं. उन्होंने लखनऊ में एआई सिटी और एआई प्रज्ञा जैसी पहलों को समयानुकूल बताते हुए कहा कि ये कदम उत्तर प्रदेश को एआई-आधारित

कौन हैं वरिष्ठ पत्रकार यतेंद्र शर्मा, जिन पर भाजपा ने यूपी में खेला बड़ा दांव, क्यों सौंपा गया इतना बड़ा पद?

(जीएनएस)।

भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद कई नए नाम चर्चा में आए हैं, लेकिन जिन चेहरों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है उनमें वरिष्ठ पत्रकार यतेंद्र शर्मा भी शामिल हैं। लंबे समय से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय यतेंद्र शर्मा को भाजपा ने प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों के साथ-साथ मीडिया जगत में भी उनकी नियुक्ति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

गाजियाबाद में उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, जबकि उनके गृह क्षेत्र हाथरस के सासनी में समर्थकों ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर खुशी जताई। वर्षों तक राजनीति की खबरों को कवर करने वाले यतेंद्र शर्मा अब खुद संगठन की अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसे में लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर यतेंद्र शर्मा कौन हैं, उन्होंने पत्रकारिता में कैसी पहचान बनाई और भाजपा ने उन्हें प्रदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए क्यों चुना।

यतेंद्र शर्मा देश के जाने-माने राजनीतिक पत्रकारों में गिने जाते हैं। वे लंबे समय से न्यूज 18 में पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। पत्रकारिता के दौरान उन्होंने सत्ता, संगठन, चुनाव और सरकार से जुड़े कई बड़े घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग की है। राजनीतिक खबरों की समझ और जमीनी स्तर तक पहुंच ने उन्हें मीडिया जगत में अलग पहचान दिलाई है।

राजनीतिक रिपोर्टिंग से बनाई पहचान

यतेंद्र शर्मा का नाम उन पत्रकारों में लिया जाता है जो लंबे समय से राजनीति को करीब से कवर करते रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति से

लेकर राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों पर रिपोर्टिंग की। टीवी पत्रकारिता में उनकी पहचान एक ऐसे पत्रकार के रूप में बनी जो राजनीतिक खबरों को सरल और तथ्यात्मक तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता से संगठन तक का सफर

आमतौर पर पत्रकार और राजनीतिक संगठन अलग-अलग भूमिकाओं में दिखाई देते हैं, लेकिन यतेंद्र शर्मा का सफर अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। वर्षों तक राजनीति को देखने और समझने के बाद अब उन्हें सीधे संगठन में जिम्मेदारी मिली है। भाजपा द्वारा उन्हें प्रदेश मंत्री बनाए जाने को कई लोग उनके अनुभव और राजनीतिक समझ का सम्मान मान रहे हैं।

भाजपा ने क्यों दी यह जिम्मेदारी?

पार्टी कार्यकताओं का मानना है कि यतेंद्र शर्मा के पास राजनीतिक मामलों की गहरी समझ है। लंबे समय तक राजनीति से जुड़े मुद्दों पर काम करने के कारण उन्हें संगठन और कार्यप्रणाली का व्यापक अनुभव है। यही वजह है कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश मंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का फैसला किया। कार्यकताओं का कहना है कि उनका अनुभव संगठन को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है।

गाजियाबाद में बधाइयों का सिलसिला

यतेंद्र शर्मा गाजियाबाद के प्रताप विहार क्षेत्र के सेक्टर-11 जी ब्लॉक में रहते हैं। जैसे ही उनके प्रदेश मंत्री बनाए जाने की खबर सामने आई, उनके घर पर शुभचिंतकों का पहुंचना शुरू हो गया। स्थानीय निवासी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और परिचित लगातार उन्हें बधाई देने पहुंचे। पूरे दिन फोन कॉल और संदेशों के जरिए भी उन्हें शुभकामनाएं मिलती रहीं।

क्षेत्र के लोगों में खास उत्साह

स्थानीय लोगों का कहना है कि यतेंद्र शर्मा हमेशा लोगों से जुड़े रहे हैं। वे अपने सरल स्वभाव और सहज व्यवहार के कारण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने पत्रकारिता के दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और आम लोगों की समस्याओं को सामने लाने का काम किया। इसी कारण समाज के विभिन्न वर्गों में उनके प्रति सम्मान का भाव देखा जाता है।

सामाजिक गतिविधियों में भी रहे सक्रिय

पत्रकारिता के अलावा यतेंद्र शर्मा सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में भी भाग लेते रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, उन्होंने समय-समय पर ऐसे मुद्दों को उठाया जिनका सीधा संबंध आम जनता से था। कई बार उन्होंने उन समस्याओं पर भी आवाज उठाई जिन्हें लोग लंबे समय से नजरअंदाज किया जाना मानते थे।

आरडब्ल्यूए ने जताई खुशी

प्रताप विहार सेक्टर-11 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यतेंद्र शर्मा को प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है।

पदाधिकारियों का मानना है कि समाज और जनता से जुड़े विषयों पर लगातार काम करने वाले व्यक्ति को संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलना सकारात्मक संकेत है।

सासनी में समर्थकों ने मनाया जश्न

यतेंद्र शर्मा मूल रूप से हाथरस जिले के सासनी क्षेत्र के निवासी हैं। उनकी नियुक्ति की खबर वहां पहुंचते ही भाजपा कार्यकताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया। उनके आवास पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कई स्थानों पर मिठाइयां बांटी गईं और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की गई। कार्यकताओं ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात बताया।

पार्टी कार्यकताओं ने जताया आभार

भाजपा कार्यकताओं ने इस फैसले के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। उनका कहना है कि संगठन ने ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है जिसने अपने क्षेत्र में मेहनत और लगन से पहचान बनाई है। कार्यकताओं का मानना है कि यतेंद्र शर्मा संगठनात्मक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।

'चटपटी बातें चुनकर खबर मत बनाइए' सुवेंदु अधिकारी की तारीफ पर विवाद बढ़ा तो भड़कीं महुआ मोइत्रा

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर चल रही खींचतान और बगावत को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच TMC सांसद महुआ मोइत्रा का एक बयान सुर्खियों में आ गया, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ अपने रिश्ते के बारें में खुल कर बात की थी।

इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगीं की क्या ममता की फायर ब्रांड नेता महुआ भी बागियों के गुट में शामिल होंगी। अब महुआ मोइत्रा ने खुद सामने आकर अपनी बात साफ की है।

महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनके इंटरव्यू के कुछ हिस्सों को चुनकर सनसनीखेज तरीके से पेश किया गया। उनका कहना है कि पूरी बातचीत को नजरअंदाज कर केवल कुछ "चटपटे हिस्सों" को उछाला गया ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके।

BBC हिंदी और बांग्ला को दिए एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने टीएमसी में चल रही अंदरूनी नाराजगी और बगावत पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ते समय अपना रुख साफ रखा था और इसी बात का वह सम्मान करती हैं।

महुआ ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी

को यह समझ आ गया था कि जब तक अभिषेक बनर्जी पार्टी में प्रभावशाली भूमिका में रहेंगे, तब तक पार्टी का नियंत्रण उनके हाथ में नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर पार्टी छोड़कर बीजेपी का रास्ता चुना और पांच साल तक अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ी। महुआ के मुताबिक, "किसी व्यक्ति से राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर वह अपनी स्थिति स्पष्ट रखता है तो उसमें सम्मान करने जैसी बात होती है।"

बागी नेताओं पर साधा निशाना

महुआ मोइत्रा ने TMC छोड़ने या नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो नेता आज अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, वे पहले भी उसी नेतृत्व में चुनाव लड़ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी आज पार्टी में नई भूमिका में नहीं आए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी वह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे और पार्टी ने उनके नेतृत्व में शानदार जीत हासिल की थी।

महुआ ने सवाल किया कि अगर नेताओं को अभिषेक की कार्यशैली से दिक्कत थी तो उन्होंने पहले यह बात क्यों नहीं कही। चुनाव जीतने और पद हासिल करने के बाद अचानक विरोध करना राजनीतिक पाखंड जैसा लगता है।

ममता बनर्जी के समर्थन में उतरीं महुआ

इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने स्पष्ट कहा कि वह पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर चर्चा और असहमति की हमेशा गुंजाइश रही है। महुआ ने बताया कि उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव बिना किसी बाहरी राजनीतिक सलाहकार संस्था की मदद के लड़ा था। इससे साबित होता है कि पार्टी में हर नेता को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी नेता को पार्टी के कामकाज से परेशानी है तो वह पार्टी छोड़ सकता है, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की लोकप्रियता के सहारे चुनाव जीतने के बाद उन्हीं पर हमला करना सही नहीं है।

महुआ मोइत्रा ने इंटरव्यू में अपने और सुवेंदु अधिकारी के पुराने संबंधों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि दोनों एक समय अच्छे दोस्त थे और राजनीति के शुरूआती दौर में सुवेंदु ने उनकी काफी मदद की थी।

महुआ ने याद किया कि जब उन्होंने करीमपुर से चुनाव लड़ा था, तब प्रचार के लिए बहुत कम लोग आते थे। उस समय सुवेंदु अधिकारी उनके साथ खड़े रहे और चुनाव प्रचार में मदद की।

उन्होंने 2014 की एक घटना का भी जिक्र किया, जब उन्हें लोकसभा टिकट नहीं मिला था और वह काफी निराश थीं। उस समय सुवेंदु अधिकारी ने उनका हौसला बढ़ाया था।

महुआ मोइत्रा के इंटरव्यू के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि महुआ ने साफ कर दिया है कि सुवेंदु अधिकारी की तारीफ का मतलब उनके राजनीतिक विचारों का समर्थन नहीं है, बल्कि उन्होंने केवल उनके फैसले को लेकर अपनी राय रखी थी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि उनकी निष्ठा आज भी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ है।

'अगर आप दिल्ली से चुनाव लड़ें तो 10 लाख वोटों से जीतेंगी', किसने ली मेलोनी की चुटकी?

(जीएनएस)।

इटली की पीएम जार्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री Giorgia Meloni ने अपनी 2023 की भारत यात्रा से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प और मजेदार किस्सा साझा किया है। उन्होंने अपनी नई किताब "Giorgia's Vision" में बताया कि जब वह नई दिल्ली पहुंचीं तो शहर की सड़कों पर जगह-जगह उनके स्वागत में बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए थे। इन पोस्टरों को देखकर उनका पूरा प्रतिनिधिमंडल हैरान रह गया था।

मेलोनी लिखती हैं कि भारत में जिस तरह उनका स्वागत हुआ, जिससे वे काफी इंप्रेस हुईं। सड़क किनारे हर कुछ दूरी पर उनके चेहरे वाले स्वागत संदेश दिखाई दे रहे थे। यही नहीं, जब उनकी यात्रा खत्म हुई और वह वापस लौट रही थीं, तब उन्हीं पोस्टरों पर "यात्रा के लिए धन्यवाद" लिखा हुआ था।

किताब के अनुसार, इस यात्रा में इटली के उप प्रधानमंत्री Antonio Tajani भी उनके साथ मौजूद थे। दिल्ली की सड़कों पर हर तरफ मेलोनी के पोस्टर देखकर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर मेलोनी नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ लें, तो वह आराम से 10

लाख वोटों से जीत जाएंगी। यह टिप्पणी मजाक में कही गई थी, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में उनके स्वागत की भव्यता ने इटली के प्रतिनिधिमंडल को कितना प्रभावित किया था।

जॉर्जिया मेलोनी ने साल 2023 में दो बार भारत का दौरा किया था। पहला दौरा मार्च 2023 में हुआ था, जब उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित Raisina Dialogue में हिस्सा लिया था। इसके बाद वह सितंबर 2023 में भारत लौटीं और नई दिल्ली में आयोजित G20 New Delhi Summit में शामिल हुईं। इन दोनों यात्राओं ने भारत और इटली के संबंधों को नई मजबूती दी। साथ ही दोनों देशों के नेताओं के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी बेहतर तालमेल देखने को मिला।

अपनी किताब के अध्याय "Head Held High Among the World Greats" में मेलोनी ने व्यक्तिगत कूटनीति की अहमियत पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कई बार देशों के बीच रिश्ते सिर्फ आधिकारिक बैठकों से नहीं, बल्कि नेताओं के बीच बने व्यक्तिगत भरोसे और दोस्ती से भी मजबूत होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi और जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय रही है। दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होते रहे हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों के नाम को मिलाकर "Melodi" नाम भी दे दिया था, जो काफी ट्रेंड हुआ।

मेलोनी का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध केवल औपचारिक बैठकों और समझौतों तक सीमित नहीं होते। कई बार कॉफी पर हुई छोटी बातचीत, कोई मजेदार किस्सा या व्यक्तिगत अनुभव भी देशों के बीच मौजूद दूरियों को कम कर सकता है। उनकी मानें तो, नेताओं के बीच बना पर्सनल ट्रस्ट कई बार जटिल राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाता है।

किताब में मेलोनी ने कई अन्य वैश्विक नेताओं से जुड़ी यादगार घटनाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि Kais Saied ने एक लंबी बैठक के बाद उन्हें समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए अपने आवास पर आने का न्योता दिया था। वहीं Aleksandar ने उनके जन्मदिन पर संतरी रंग के गुलाब भेंट किए थे। इसके अलावा Edi Rama के साथ अपनी गहरी दोस्ती का भी उन्होंने उल्लेख किया है।

बेटी के लिए मिला 'Hello Kitty' गिफ्ट

मेलोनी ने यह भी बताया कि Fumio Kishida ने हिरोशिमा में हुए G7 सम्मेलन के दौरान उनकी बेटी के लिए 'Hello Kitty' डॉल गिफ्ट की थी। वहीं पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री Mateusz Morawiecki उन्हें एक ऐसे कैफे में लेकर गए थे, जो उनकी पसंदीदा किताबों की सीरीज The Lord of the Rings की थीम पर आधारित था।

किताब में दिखी कूटनीति की मानवीय तस्वीर

मेलोनी का कहना है कि कूटनीति सिर्फ राजनीतिक हितों का खेल नहीं है। इसमें सम्मान, विश्वास, दोस्ती और मानवीय जुड़ाव की भी बड़ी भूमिका होती है। भारत में मिला शानदार स्वागत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती इसी बात का उदाहरण है।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

अयोध्या रवाना होने से पहले केजरीवाल के गंभीर आरोप, कहा- 'राम मंदिर में अरबों का चढ़ावा गायब, एसआईटी सिर्फ धोखा'

अयोध्या रवाना होने से पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए।

(जीएनएस)।

लखनऊः अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए रवाना होने से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर में कथित चंदा और चढ़ावे की चोरी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़े मामले में अब तक न तो एफआईआर दर्ज हुई है और न ही निष्पक्ष जांच होती दिखाई दे रही है।

केजरीवाल ने कहा कि उनका मन इस पूरे मामले से बेहद दुखी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान राम की पादुका, हार, दीपक, गहने, हीरे-जवाहरात और चढ़ावे तक की चोरी हुई है। उन्होंने दावा किया

कि मंदिर से 200 करोड़ रुपये नकद और 200 किलो चांदी भी गायब हुई है।

'कल प्रभु श्रीराम के दर्शन करने जाऊंगा'

अरविंद केजरीवाल ने कहा, ह्नकल मैं अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के दर्शन करूंगा। श्रीराम मंदिर जाऊंगा, हनुमानगढ़ी जाऊंगा और संतों से भी मुलाकात करूंगा।ह्व उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में अरबों रुपये की कथित गड़बड़ी की बातें सामने आई हैं, जिससे देशभर के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

एफआईआर नहीं तो एसआईटी किस कानून के तहत?

अरविंद केजरीवाल ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यदि इतनी बड़ी चोरी हुई है तो अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई।

बिना एफआईआर के SIT कैसे बन सकती है? यह SIT किस कानून के तहत गठित की गई है? यह केवल एक दिखावा है। इसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल

'बड़े लोगों को बचाने की कोशिश'

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि रक्ळ का मुख्य उद्देश्य मामले में शामिल प्रभावशाली लोगों को बचाना है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कथित चोरी बिना बड़े लोगों के संरक्षण के संभव नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा, यह कोई साधारण मामला नहीं है बल्कि बेहद गंभीर और संगीन मामला है। इसमें बड़े-बड़े लोगों की भूमिका की आशंका है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

लखनऊ अग्निकांड : वीरेन्द्र प्रसाद ने फर्जी एनओसी से लिया था बिजली कनेक्शन, साल 2016 से किसी जिम्मेदार ने नहीं की कार्रवाई

(जीएनएस)।

लखनऊ। अलीगंज में जिस अवैध निर्माण में आग लगी थी, उसके कमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए भवन स्वामी ने मिलीभगत करके फर्जी एनओसी ली थी। यह एनओसी विद्युत सुरक्षा निदेशालय के तत्कालीन सहायक निदेशक पीके निगम के फर्जी हस्ताक्षर से तैयार की गई थी। यह खुलासा विद्युत सुरक्षा निदेशालय के निदेशक गिरीश कुमार सिंह ने किया है।

गिरीश के मुताबिक वर्ष 2022 से पहले आफलाइन एनओसी जारी करने की प्रकिया थी। अग्निकांड के बाद अलीगंज सेक्टर डी -102 के रिकार्ड देखे गए तो वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला के नाम की कोई एनओसी क्रमांक संख्या 26 में नहीं मिली। क्रमांक संख्या 26 में दूसरे उपभोक्ता के नाम एनओसी जारी की गई है।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय के रिकार्ड में कोई ब्योरा नहीं

कुल मिलाकर विद्युत सुरक्षा निदेशालय के रिकार्ड में वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला का कोई ब्योरा नहीं मिला। निदेशालय ने उच्च अधिकारियों को भी इसे पूरे मामले की जानकारी भेज दी है। वहीं सवाल खड़ा होता है क्या ऐसी फर्जी एनओसी शहर की अन्य बिल्डिंगों के लिए तैयार तो नहीं की गई होगी? इस पूरी कार्यप्रणाली को लेकर बिजली विभाग और विद्युत सुरक्षा निदेशालय पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दोनों विभागों के बीच ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि उपभोक्ता के वाणिज्यिक कनेक्शन का आवेदन करते ही निदेशालय को पता हो जाए। निदेशालय से एनओसी लेने के लिए उपभोक्ता को नए सिरे से पूरी प्रकिया अपनानी पड़ती है। अभी तक विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जिम्मेदारी जो ठहराई जा रही थी, उससे निदेशालय ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया है कि जब उसके यहां से एनओसी ही नहीं जारी की गई तो कैसे उसे पता चलेगा कि नवीनीकरण कराने का समय पूरा हो गया है या नहीं ?

मध्यांचल में 57 हजार कमर्शियल कनेक्शन दस किलोवाट से ऊपर

मध्यांलच में 57 हजार कमर्शियल कनेक्शन दस किलोवाट से ऊपर हैं। वहीं लखनऊ में दस किलोवाट या उससे ऊपर भार वाले कनेक्शनों की संख्या 10,706 हैं। सवाल खड़ा होता है क्या इनमें कई एनओसी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला की तरह फर्जी तो नहीं बनाई गई होंगी। इस पर बिजली विभाग व निदेशालय के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।

स्थायी कनेक्शन लेकर ही बनवाया था वीरेंद्र ने मकान, जो नियमानुसार है गलत

जिस कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, उसके निर्माण में अस्थाई बिजली कनेक्शन देने के बजाए सीधे स्थाई कनेक्शन एक किलोवाट का जारी कर दिया गया था।नियमानुसार स्थायी कनेक्शन से मकान का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जब कनेक्शन दिया गया, उस समय पुरनिया बिजली उपकेंद्र के तत्कालीन जेई विरेंद्र सिंह, एसडीओ शैलेश शर्मा व डालीगंज खंड के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार वर्मा थे, इनकी जांच भी शुरू हो सकती है।

यहीं नहीं, एक किलोवाट बिजली कनेक्शन को चंद माह बाद सीधे 20 किलोवाट लोड आवासीय में कर दिया गया था। फिर अपने कनिष्ठों की रिपोर्ट को सही मानते हुए तत्कालीन अधिशासी अभियंता अशोक ने बीस किलोवाट आवासीय कनेक्शन को कमर्शियल में वर्ष 2016 में कर दिया था। इसमें फर्जी विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी लगा दी गई थी।

मेरे पास जो एनओसी है, वह असली है या नकली, मुझे. नहीं पता, उस पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय लिखा हुआ है। मैने कोई उसकी जांच नहीं कराई है। निदेशक क्या कह रहे हैं, वहीं बता सकते हैं।

-वीपी सिंह, मुख्य अभियंता, जानकीपुरम जोन

'कांग्रेस-सपा ने संविधान का जितना अपमान किया, उतना किसी ने नहीं किया...', विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे किस मुंह से लोकतंत्र की बात करते हैं और संविधान की प्रतियां लेकर घूमते हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसी ने संविधान का अपमान नहीं किया है.

(जीएनएस)।

सीएम योगी ने संत कबीर नगर जिले में 475 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 139 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए यह टिप्पणी की. उन्होंने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जून भारत के इतिहास में एक काला दिन है क्योंकि इसी दिन कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू कर लोकतंत्र का गला घोंट दिया था.

उन्होंने कहा कि नागरिकों के

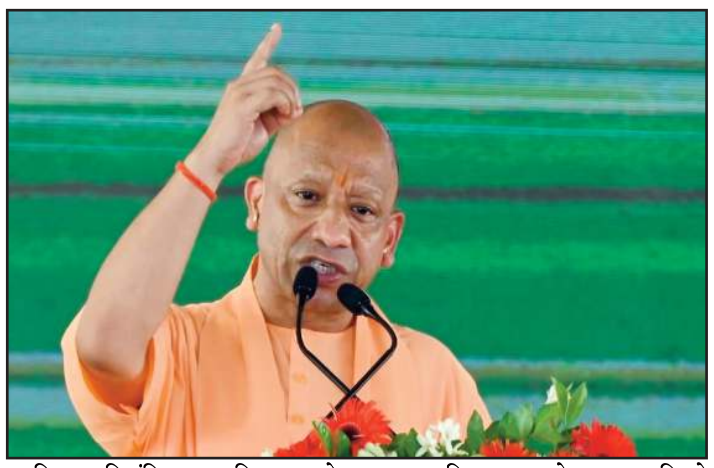

अधिकार निलंबित कर दिए गए थे. न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था और मीडिया पर प्रतिबंध लगाए गए थे. जो लोग आज संविधान की प्रतियां लेकर घूमते हैं और लोकतंत्र की रक्षा का दावा करते हैं, उन्हें 25 जून 1975 को हुई घटनाओं को याद रखना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे किस मुंह से लोकतंत्र की बात करते हैं और संविधान की प्रतियां लेकर घूमते हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसी ने संविधान का अपमान नहीं किया है.

आदित्यनाथ ने कहा कि आपातकाल के दौरान तानाशाही शासन का विरोध करने पर कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था. इनमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, राज नारायण, मुलायम सिंह यादव, चंद्र शेखर और चौधरी चरण सिंह जैसे नेता शामिल थे.

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी डबल इंजन सरकार बीआर आंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही है और समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है.

उन्होंने बताया कि दिन में उन्होंने लखनऊ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ एक बैठक में भाग लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अगले चरण के तहत 6.18 लाख आवास आवंटित किए गए. उन्होंने जनसभा के आखिरी में लोगों से बीजेपी की डबल इंजन सरकार के विकास एजेंडे का समर्थन करने की अपील की.

मुख्यमंत्री योगी धनघटा में 224.79 करोड़ रुपए की 65 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन-शिलान्यास

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संत कबीर नगर जिले के धनघटा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह 224.79 करोड़ रुपए की लागत वाली 65 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और जन-कल्याणकारी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बैजनाथधाम शिव मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम करीब 4 बजे हैंसर बाजार ब्लॉक के बसवारी गांव स्थित बैजनाथधाम शिव मंदिर पहुंचेंगे। यहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे और स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे।

17 परियोजनाओं का उद्घाटन, 48 का शिलान्यास

अधिकारियों के अनुसार कुल 65 परियोजनाओं में से 54.42 करोड़ रुपए की लागत वाले 17 विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं 170.37 करोड़ रुपए की लागत वाली 48 नई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इन योजनाओं से क्षेत्र के समग्र

विकास और जन-सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।

कार्यक्रम से पहले तैयारियों का निरीक्षण

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले धनघटा के विधायक गणेश चौहान ने बुधवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुरक्षा, पार्किंग और हेलीपैड व्यवस्था पर जोर

निरीक्षण के दौरान पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन योजना, सुरक्षा इंतजाम और हेलीपैड की तैयारियों का जायजा लिया गया। विधायक गणेश चौहान ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर और सुचारू रूप से पूरी करने के निर्देश दिए।

जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कीं

मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियों में तेजी ला दी है। सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है।

डीएम और एसपी खुद कर रहे निगरानी

जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा स्वयं तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रहा है कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सुरक्षा और अन्य सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हों।

तीन एसडीएम को सौंपी गई जिम्मेदारी

जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं के समन्वय और निगरानी के लिए विशेष रूप से तीन उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) की तैनाती की गई है, ताकि आयोजन सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

'मुलायम सिंह कहते थे कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए', सीएम योगी ने घेरा, सपा ने दिया जवाब

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग संविधान की प्रतियां लेकर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इनके दोहरे चरित्र को जनता के सामने उजागर करने की जरूरत है. इस पर सपा ने पलटवार किया है.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव को घेरा है. इसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है.

समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स हैंडल पर लिखा, "जो कभी आपको भीख मंगवाने के दावे करता था, आज उसे मन मारकर आपको अपना साथी मंत्री बनाना पड़ा है, अपने साथ कुर्सी पर बिठाना पड़ा है और मजे की बात ये कि वो अभी भी आपको वहीं कहीं भेजने के लिए शिद्दत से प्रयासरत है. है ना मजे की बात आदित्यनाथ जी?"

योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर हमला

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा, "जो लोग संविधान की प्रतियां लेकर

घूम-घूमकर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इनके दोहरे चरित्र को जनता के सामने उजागर किए जाने की जरूरत है. उस समय इंदिरा गांधी के अत्याचार के कारण जो लोग लोकतंत्र के समर्थन में जेल की यात्रा कर रहे थे. इंदिरा गांधी के आदेश से उस अत्याचार की चपेट में पिस रहे थे, ऐसे लालू प्रसाद यादव जी हो, मुलायम सिंह यादव हों, इनकी वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है? आज उसी कांग्रेस के साये में राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं."

ये मुलायम सिंह की विरासत को डूबोने के लिए उतारू- सीएम योगी

उन्होंने आगे कहा, "जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रयास करती थी तो मुलायम सिंह यादव उसका विरोध करते थे. कहते थे कि सबकुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं? उनका आचरण देख लीजिए. वो कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवार होकर मुलायम सिंह की विरासत को भी डूबोने के लिए उतारू हैं. कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनकी भी लोकतंत्र में कोई निष्ठा नहीं है.

सपा-कांग्रेस साथ जुड़कर लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं- योगी

मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाते हुए कहा, "इनकी जब सत्ता थी तो इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था. इन्होंने भी सभी संस्थाओं पर हमला किया था. ये कार्यपालिका, न्यायपालिका या प्रेस पर बराबर हमला करते थे. ये किसी का सम्मान नहीं करते थे. इसलिए अपने समान उद्देश्य के लिए आज भी एक दूसरे के साथ जुड़कर देश के लोकतंत्र को कमजोर करने, परिवारवाद की राजनीति को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत के संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत आचरण करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं."

सीएम योगी का तीन दिवसीय दौरा आज, गोरखपुर, संतकबीर नगर और देवरिया में देंगे करोड़ों की सौगात

(जीएनएस)।

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन दिवसीय दौरे पर गुरुवार की शाम करीब पांच बजे गोरखपुर आएंगे। इससे पहले शाम चार बजे संतकबीर नगर के हैसर बाजार ब्लाक के बसवारी गांव स्थित बैजूनाथधाम शिव मंदिर पहुंचेंगे। वहां जनसभा को संबोधित करने के साथ धनघटा विधानसभा क्षेत्र की 224.79 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे।

वहां से गोरखपुर पहुंचने के बाद चिलुआताल स्थित अक्षय पात्र के नए केंद्रीयकृत रसोई घर का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री देवरिया के बरांव में आयोजित कार्यक्रम में रुद्रपुर व बरहज विधानसभा क्षेत्र की 456.38 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे।

गोरखपुर लौटने के बाद अपराह्न करीब तीन बजे बेतियाहाता में एक निजी हास्पिटल का लोकार्पण करेंगे। तीसरे दिन शनिवार की सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री, मेडिकल कालेज रोड स्थित एक रिजार्ट में आयोजित भाजपा के महानगर प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम करीब पांच बजे वह चिलुआताल स्थित अक्षय पात्र के नए केंद्रीयकृत रसोई घर का उद्घाटन करेंगे। रात को मुख्यमंत्री विकास परियोजनाओं की प्रगति और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी कर सकते हैं। अगले दिन मुख्यमंत्री सुबह करीब दस बजे देवरिया जाएंगे, जहां वह लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे।

देवरिया से लौटकर वह गोरखपुर आएंगे और फिर दोपहर बाद बेतियाहाता में एक निजी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद तीसरे दिन शनिवार की सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज रोड स्थित एक रिजॉर्ट में भाजपा के महानगर प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

उधर, आगामी 27 एवं 28 जून को आयोजित होने वाले भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 को सफल बनाने के लिए संचालन समिति ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर ही बैठक की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष त्रयम्बकेश त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता व संचालन समिति प्रमुख क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजिताशु सिंह आशू, राजेश गुप्ता, ओम प्रकाश शर्मा, इंद्रमणि उपाध्याय, अच्युतानंद शाही, बृजेश मणि मिश्रा, पवन यादव, शिवम पाण्डेय सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 10 हजार श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, लखनऊ से 40 सेवादारों का पहला जत्था रवाना

(जीएनएस)।

लखनऊ। बाबा अमरनाथ बफार्नी की यात्रा का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे सेवादारों और भंडारों की तैयारियों में तेजी आ रही है। यात्रियों की सेवा के लिए सेवादारों का 40 सदस्यीय पहला जत्था गुरुवार को तिलकनगर से रवाना किया।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमीनाबाद के श्री अमरनाथ सेवा संस्थान के महामंत्री ओम प्रकाश ओमी ने बताया कि एक जुलाई से मनीगाम में भंडारा लगेगा। रवानगी के पहले तिलकनगर में भंडारा भी हुआ।

तीन जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली यह यात्रा इस बार 57 दिनों की होगी। भंडारे में हर दिन तीन से पांच हजार श्रद्धालुओं को निश्शुल्क प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। राजधानी से 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है।

आलमबाग स्थित मौनी बाबा मंदिर से नंदी श्री गौरी शंकर अमरनाथ सेवा संस्थान की ओर से पहलगाम के लिए भंडारे की सामग्री और सेवादारों का पहला जत्था रवाना किया गया। यात्रा संयोजक शिवकुमार बाबा ने बताया कि पूरे यात्रा काल में पहलगाम में विशाल भंडारे का संचालन कर देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को निश्शुल्क भोजन व अन्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि सेवादारों की पहली टोली भी रवाना हो चुकी है। राजाजीपुरम स्थित श्री बाबा अमरनाथ बफार्नी सेवा मंडल की ओर से भी बालटाल और पंचतरनी के लिए भंडारे की रसद भेजी गई। मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष नवीन अरोड़ा ने बताया कि शिवभक्तों के लिए भोजन के साथ आवास, दवाओं तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

मनकामेश्वर मंदिर की महंत देव्या गिरि ने बताया कि अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। यही कारण है कि अमरनाथ यात्रा सनातन आस्था, तप, त्याग और सेवा का महापर्व मानी जाती है।

कौन हैं कन्नड़ एक्ट्रेस कृषि थापांडा, जिनके बेंगलुरु वाले घर में फंदे से लटकी मिली बिजनेसमैन की लाश?

(जीएनएस)।

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री कृषि थापांडा अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। इसकी वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि उनके बेंगलुरु स्थित घर में हुई एक चौंकाने वाली घटना है। दरअसल, वैशाख नाम के एक कारोबारी ने कथित तौर पर अभिनेत्री के घर पर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है और कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

इस बीच लोगों के मन में एक सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर कृषि थापांडा कौन हैं और उनका फिल्मी सफर कैसा रहा है। कन्नड़ सिनेमा में अपनी पहचान बना चुकी कृषि अब इस मामले के कारण चर्चा के केंद्र में हैं। आइए

जानते हैं उनके करियर और हालिया विवाद से जुड़ी पूरी कहानी।

कौन हैं कृषि थापांडा?

कृषि थापांडा कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने मनोरंजन जगत में अपनी पहचान मॉडलिंग से बनाई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और कई कन्नड़ फिल्मों में नजर आईं। सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। फैशन, लाइफस्टाइल और ग्लैमर से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो वह अक्सर अपने प्रशंसकों के साथ साझा करती रहती हैं।

फिल्मों और मॉडलिंग में बनाई पहचान

कृषि ने अपने करियर की शुरूआत मॉडलिंग असाइनमेंट्स से की थी। धीरे-धीरे उन्हें फिल्मी दुनिया में काम मिलने लगा। उन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया और युवा दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई।

14 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड बंगाल से गिरफ्तार, निवेशकों की शिकायत पर लखनऊ में दर्ज है मुकदमा

(जीएनएस)।

लखनऊ। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) ने निवेशकों के 14 करोड़ रुपये ठगने वाले गिरोह के मास्टर माइंड रोहित कुमार उपाध्याय को बंगाल के खड़गपुर से गिरफ्तार किया है।

आरोपित के खिलाफ लखनऊ के आलमबाग थाने में निवेशकों की शिकायत पर वर्ष 2017 में मुकदमा दर्ज किया गया था। बस्ती के खेरिया बाजार निवासी आरोपित ने दिल्ली, हरियाणा, कानपुर के कई निवेशकों के साथ ठगी की थी।

आरोपित ने पियर्स एलाइड कारपोरेशन लिमिटेड व डिपियर्स एलाइड कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से विभिन्न जिलों में कार्यालय खोले थे। रिजर्व बैंक की मंजूरी के बिना दोनों कंपनियों के निदेशकों के साथ मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज के जरिए निवेशकों से आरडी व एफडी खातों में 14 करोड़ रुपये जमा कराए थे।

निवेशकों के साथ ठगी के लिए आरोपितों ने कम समय में धन दोगुणा करने का लालच दिया था। साथ ही निवेशकों को कूटरचित बांड एवं रसीदें प्रदान कर उनका विश्वास हासिल किया और बाद में कंपनी की लखनऊ, बिजनौर एवं अन्य जिलों में खोली शाखाएं बंद कर फरार हो गए। ईओडब्ल्यू की जांच में ठगी के इस मामले में रोहित कुमार उपाध्याय की संलिप्तता प्रकाश में आई।

इसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। आरोपित के खिलाफ बिहार पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज किया था। ईओडब्ल्यू की टीम को आरोपित के बंगाल में होने की सूचना मिली तो टीम ने खड़गपुर में दबिश देकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

आईआईएम लखनऊ ने शुरू किया एआई और बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स, मेधावियों को फीस में मिलेगी छूट

(जीएनएस)।

लखनऊ। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), लखनऊ में नए सत्र से 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए चार वर्षीय बैचलर ऑफ साइंस (बीएस) इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स पाठ्यक्रम की शुरूआत होगी।

इसमें 60 सीटों के सापेक्ष अब तक 450 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें जेईई एडवांस्ड के टॉप 100 रैंक वाले भी शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तीन जुलाई है। ऐसे में इस कोर्स में प्रवेश को लेकर कड़ा मुकाबला होगा।

आइआइएम लखनऊ के निदेशक प्रो. एमपी गुप्ता ने कहा कि यह पाठ्यक्रम प्रतिभाशाली युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। किसी प्रबंधन संस्थान में पहली बार विद्यार्थियों का प्रवेश जेईई एडवांस्ड के आधार पर किया जाएगा। इसमें 60 सीटों के सापेक्ष काफी आवेदन आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस कोर्स में मेधावी अभ्यर्थियों के लिए फीस में विशेष छूट देने का भी तैयारी की जा रही है। संस्थान में प्रोग्राम एसोसिएट शुभम वैश्य से बताया कि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का वर्ष 2025 या 2026 में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के साथ जेईई एडवांस्ड 2026 में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है।

चयन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन और जेईई एडवांस्ड स्कोर के आधार पर किया जाएगा। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तीसरे वर्ष की सफलतापूर्वक पढ़ाई पूरी करने के बाद पात्र विद्यार्थी वर्ष 2027-28 से शुरू होने वाले टेक-एमबीए कार्यक्रम में प्रवेश लेकर इसे एकीकृत ड्यूल-डिग्री कार्यक्रम में परिवर्तित कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन की अंतिम तिथि : तीन जुलाई, प्रथम चयन सूची : 10 जुलाई

द्वितीय चयन सूची 23 जुलाई

रिपोर्टिंग एवं पंजीकरण : 17 अगस्त

शैक्षणिक सत्र प्रारंभ : 18 अगस्त

यूपी में होगा 50 हजार करोड़ का निवेश, सीएम योगी की मौजूदगी में 15 कंपनियों के साथ हुआ एमओयू

सीएम योगी की मौजूदगी में बुधवार को बेंगलुरु में 15 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ। ये कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अन्य सेक्टर में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगी।

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में बुधवार को बेंगलुरु में 15 कंपनियों के साथ एमओयू हुआ। ये कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, आईटी और आईटीईएस और एफडीआई सेक्टर में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगी।

मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश की 36 से अधिक सेक्टोरल नीतियां निवेशकों को व्यापक अवसर प्रदान कर रही हैं। राज्य सरकार उद्योगों के लिए सुरक्षित, सहयोगी और विकासोन्मुख वातावरण उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने निवेशकों को सुरक्षा, आकर्षक सब्सिडी और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से त्वरित अनुमोदन का भरोसा दिलाया।

कहां होगा निवेश

एलजी, इनमोबी, अमेरिप्राइज, एओएन, मेटलाइफ और टेबलस्पेस प्रदेश में नए ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) स्थापित करेंगी। टीमलीज कंपनी जीसीसी सेक्टर में रोजगार मुहैया करवाने के लिए युवाओं के स्किल डिवलेपमेंट में सहयोग करेगी। ऐस इंटरनैशनल लिमिटेड ने डेयरी विनिर्माण, एबी इनबेव ने ब्रूइंग, मैपलेट्री ने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिर्मा ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश की घोषणा की। केन्स ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण में विस्तार की घोषणा की। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि 2031 तक चार करोड़ वर्गफुट ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस क्षेत्र विकसित किया जाएगा। प्रदेश में 500 जीसीसी इकाइयों को स्थापित किया जाएगा।

जानिए क्या है प्लान

प्रेसटीज ग्रुप 15,000 करोड़ लगाकर बिजनेस पार्क विकसित करेगा

हॉरिजोन (ब्लैकस्टोन) भी 10,000 करोड़ से बिजनेस पार्क बनाएगा

5,000 करोड़ का निवेश कर रहेजा - माइंडस्पेस बिजनेस पार्क बनाएगा

5,000 करोड़ का निवेश कर एंबेसी ग्रुप बिजनेस पार्क विकसित करेगा

4,000 करोड़ से सत्वा डिवेलपर्स प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा

'मुहर्रम- चौथा शनिवार और रविवार', क्या 3 दिन लगातार बंद रहेंगे बैंक?

(जीएनएस)।

आज 'मुहर्रम' है, इसलिए कई राज्यों में बैंक बंद हैं, मोहर्रम की यह छुट्टी पूरे देश में एक समान नहीं है, क्योंकि बैंक अवकाश राज्यवार फ्ह्वक की सूची के अनुसार तय होते हैं। फ्ह्वक के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, 26 जून को बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रायपुर, रांची समेत कई शहरों में बैंक बंद हैं, तो वहीं कुछ राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

26 जून से शुरू हुआ लंबा बैंक वीकेंड

26 जून 2026 को शुक्रवार के दिन मुहर्रम का अवकाश है। इसके बाद 27 जून को चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों में नियमित छुट्टी रहेगी, जबकि 28 जून को साप्ताहिक अवकाश (रविवार) रहेगा। इस वजह से कई राज्यों में बैंक शाखाएं लगातार तीन दिनों तक बंद हैं।

किन राज्यों में 3 दिन बंद हैं बैंक?

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा

ग्राहकों को क्या-क्या दिक्कत हो सकती है?

लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद रहने से उन ग्राहकों को परेशानी हो सकती है जिन्हें बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर की जरूरत हो या लॉकर संचालन करना हो या फिर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना हो, इसके अलावा जिन्हें केवाईसी दस्तावेज या चेक को जमा करना है, उन्हें दिक्कत हो सकती है।

ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू

हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। ग्राहकों को निम्न सुविधाएं मिलती रहेंगीः

UPI भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप, NEFT ट्रांसफर, RTGS ट्रांजैक्शन, क्ट्ठर सेवा, एटीएम से नकदी निकासी

आरबीआई कैसे तय करता है बैंक छुट्टियां?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंक अवकाशों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता हैः

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एवं RTGS अवकाश, बैंक खातों के समापन से संबंधित अवकाश

मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना

मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसे मुस्लिम समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र है। यह महीना विशेष रूप से 10वीं तारीख, यानी आशूरा, के कारण महत्वपूर्ण है। इस दिन 680 ईस्वी में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने इराक के कर्बला में सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मुहर्रम का महीना शोक, आत्मचिंतन, त्याग और धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है।

साहस, बलिदान और इंसानियत का पर्व है मुहर्रम

शिया मुस्लिम समुदाय इमाम हुसैन की शहादत की याद में मजलिस और जुलूस का आयोजन करता है। मुहर्रम का संदेश अन्याय के खिलाफ खड़े होने, सत्य का साथ देने और मानव मूल्यों की रक्षा करने का है। यही कारण है कि मुहर्रम केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और इंसानियत की मिसाल के रूप में भी याद किया जाता है।

सीएम भगवंत मान का वीडियो था फर्जी, पूरी साजिश का पदार्फाश

(जीएनएस)।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का फर्जी वीडियो बनाने की पूरी साजिश का पदार्फाश हो गया। जिस वीडियो लेकर विरोधी हल्ला मचा रहे थे, असल में वह फर्जी निकला। सीएम भगवंत मान के जैसा दिखने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया गया। कनाडा में बैठे ब्लैकमेलर जगमन समरा ने भगवंत मान के मास्क के साथ वीडियो बनाया था।

कार में मास्क की डिलीवरी होने के बाद हाथ में भगवंत मान के मास्क के साथ जगमन समरा वीडियो में दिख रहा है। फर्जी वीडियो में चेहरे पर मास्क साफ दिख रहा है और भगवंत मान के गले पर मौजूद ऑपरेशन का निशान भी गायब है।

फर्जी वीडियो की साजिश का पदार्फाश खुद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली क्लब में प्रेसवार्ता करके की। इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहीं विरोधी पार्टियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर कहा कि फर्जी वीडियो का सारा सच बाहर आ गया है। भगवंत मान का फर्जी वीडियो मास्क लगवाकर बनाया गया था। अब ये ईडी पार्टी, चिट्टा पार्टी और झगड़ा पार्टी पंजाब में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। पंजाब के लोग इस घटिया हरकत के लिए इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।

'मुझे धार्मिक तौर पर बदनाम करना है'

उधर, प्रेसवार्ता के दौरान सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले कई दिनों से मेरी एक नकली और फर्जी वीडियो चला-चलाकर उससे सियासी लाभ लेने के लिए धार्मिक हुक्मनामे भी जारी करवाए गए हैं। जिन सियासी आकाओं ने धार्मिक पदों पर बैठे लोगों को अपनी सुविधानुसार घोषणाएं करने को कहा है, उनका मुख्य मकसद मुझे धार्मिक तौर पर बदनाम करना है क्योंकि राजनीतिक तौर पर वे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वे ग्राउंड पर बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। वे अब इस स्तर तक गिर गए हैं कि हर रोज कोई न कोई ऐसा हुक्म या आदेश जारी करते हैं जिससे मुझे धार्मिक तौर पर बदनाम किया जा सके।

सारी पार्टियां मिलकर मेरे पीछे पड़ गई हैं: भगवंत सिंह मान

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से जितने काम हमारी सरकार ने किए हैं, उतने किसी और ने नहीं किए। चाहे वह बेअदबी के खिलाफ सख्त सजा का कानून बनाना हो, पालकी साहिब वाली गाड़ी का सारा टैक्स माफ करना हो, श्री आनंदपुर साहिब में विधानसभा सत्र बुलाना हो या गुरु साहिब के चरणों में शहीदी दिवस के अवसर पर तीन शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देना हो, ये विरोधी इन कामों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब सारी पार्टियां मिलकर मेरे पीछे पड़ गई हैं और उनका एक ही मकसद है कि बस भगवंत मान को टारगेट करो, झूठी- सच्ची वीडियो बनाकर लोगों के दिमाग में यह बात डाल दो ताकि लोग मुझसे नफरत करने लगें, लेकिन यह संभव नहीं होगा।

'भगवंत मान का बायकॉट करो, उसे मुंह मत लगाओ'

भगवंत सिंह मान ने कहा कि एसजीपीसी वाले गुरुद्वारा साहिबों के आगे मेरे बायकॉट के बोर्ड लगा रहे हैं और आदेश दे रहे हैं कि अकाल तख्त साहिब का हुक्म है (जिसे मैं और सारी दुनिया सर्वोच्च मानती है) कि भगवंत मान का बायकॉट करो, उसे मुंह मत लगाओ। लेकिन यही बोर्ड सुखबीर बादल के लिए क्यों नहीं लगाए गए, जब उन्हें तनखैया करार दिया गया था? जिन लोगों ने सुखबीर बादल का 2 दिसंबर को हां-में-हां मिलाया था, उनके बायकॉट के बोर्ड क्यों नहीं लगे कि ये बेअदबी के दोषी हैं, गोलियां चलाने के लिए जिम्मेदार हैं या गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में पानी की बौछारें कराने के जिम्मेदार हैं? जब एसजीपीसी का प्रधान खुद कहता है कि वह गुरु गोबिंद सिंह का नहीं, बल्कि सुखबीर बादल का सिपाही है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके आका कौन हैं?

'मैं अकाल तख्त साहिब को कैसे चुनौती दे सकता हूं'

मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक उस फर्जी वीडियो का सवाल है, जब मुझे अकाल तख्त साहिब पर बुलाया गया था। तब मैं एक विनम्र सिख के तौर पर गया था। आज भी यदि बुलाया जाएगा तो मैं हाजिर होऊंगा। मैं अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता को चुनौती देने की कोई औकात नहीं रखता। उन्होंने वीडियो भी जारी की है। मैंने तो उन्हें लाइव करने की विनती की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि लाइव नहीं कर सकते, यह केवल पंज सिंह साहिबानों के लिए रिकॉर्डिंग रखी गई है। अब वे उस एडिटेड हिस्से को भी रिलीज करने लगे हैं। मेरी यही चुनौती है कि जहां मर्जी से इसकी जांच करा लीजिए, उस वीडियो में मैं नहीं हूं। उस वीडियो में व्यक्ति की शारीरिक संरचना मेरे साथ नहीं मिलती। उसका कद मुझसे दो इंच ऊंचा है, उसकी चाल-ढाल और खड़े होने का तरीका बिल्कुल अलग है।

'कांग्रेस कह रही है कि भगवंत मान का बायकॉट करो'

भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब ये विरोधी पार्टियां लैब वालों के पीछे पड़ गई हैं और उनसे कहलवाने लगी हैं कि रिपोर्ट फर्जी है। तीनों पार्टियां एक हो गई हैं। कांग्रेस कह रही है कि भगवंत मान का बायकॉट करो क्योंकि इसने अकाल तख्त की सर्वोच्चता को ठेस पहुंचाई है। यह वही कांग्रेस है जिसने अकाल तख्त को ढहाया और 1984 में तोपें और गोले चलाए। दूसरी पार्टी अकाली दल है जिस पर बेअदबी के आरोप हैं और तीसरी पार्टी भाजपा है जिसने इंदिरा गांधी को ब्लू स्टार ऑपरेशन के लिए उकसाया था। ये तीनों मिलकर भगवंत मान के खिलाफ साझा मोर्चा बना चुके हैं।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये लोग बौखलाए हुए हैं क्योंकि ये जनता का सामना नहीं कर सकते। मैं तो हर रोज किसी न किसी गांव में जाता हूं। गुरुवार को बुढवाडा के धरमपुरा में था, परसों मौर मंडी के मंडी कलां में था। मैं पानी, बिजली, रोजगार, तालाबों और सड़कों की बात करता हूं, लेकिन ये किसी और ही भटकाव में पड़े हैं।

सीएम भगवंत सिंह मान ने फर्जी वीडियो का सच दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि वीडियो में जो व्यक्ति मेरी जगह एक्टिंग कर रहा है, साफ दिख रहा है कि उसने मास्क पहना हुआ है। गर्दन के पास एक स्पष्ट रेखा दिखाई दे रही है जो मास्क की है। दूसरी बात, 5 साल की उम्र से मेरी गर्दन पर एक ऑपरेशन हुआ था, उसका निशान अभी भी है जो उस वीडियो में नहीं है। लोग मेरी 'जुगनू' वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी वह निशान है। वीडियो बनाने वाले यह बात भूल गए।

उन्होंने कहा कि वीडियो में कान के पास का हिस्सा, मास्क का रंग और मुड़ने का तरीका साफ बता रहा है कि वह एक प्लास्टिक का मास्क है। आंखों को छिपाने के लिए उसने काले चश्मे पहने हुए हैं, क्योंकि आंखों का मास्क नहीं बन सकता। इस मास्क की बैकग्राउंड क्या है, इसको लेकर भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। मास्क कहां से बनवाया गया, कैसे डिलीवरी ली गई और उसे पहनकर जगमन समरा नाम के ब्लैकमेलर ने वीडियो बनाई, यह सब साफ है। उसने गाड़ी में बैठे हुए हाथ पर मास्क चढ़ाकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें दिखाया गया था कि चेहरे पर चेहरा कैसे चढ़ जाता है। जगमन समरा ने हाथ पर मास्क चढ़ाकर उसे लाइव किया था।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कनाडा का मामला है। मैं तो 2016 के बाद कनाडा गया ही नहीं। 2016 में गया था, उसके बाद चुनाव लड़ा और 2019 में सांसद बन गया। उन्होंने पूछा कि होटल के कमरे में गुरु साहिब की तस्वीरें कौन लगाता है? और कमरे की बनावट 2017-18 के बाद के होटलों जैसी है। अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा वाले सोच रहे हैं कि उन्हें भगवंत मान के खिलाफ कोई बड़ा लूप होल मिल गया है। उन्होंने कहा कि उसने अरविंद केजरीवाल का मास्क भी मंगवाया है जो हम आने वाले दिनों में दिखाएंगे। हम जल्द ही यह भी खुलासा करेंगे कि इसके पीछे पैसे देने वाले स्पॉन्सर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन हैं। उसमें भी यह साझा मोर्चा शामिल है।

'ब्लैकमेलर ने मेरी कुछ पर्सनल वीडियो बनाई थीं'

भगवंत मान ने कहा कि उस ब्लैकमेलर ने उसी कमरे में मेरी कुछ और पर्सनल वीडियो भी बनाई थीं, जिनमें यह दिखाया गया था कि भगवंत मान शराब पीकर पता नहीं क्या कर रहा है। वह सब एक ही दिन में शूट किया गया था। हम यह वीडियो अकाल तख्त साहिब को भी भेजेंगे और कहेंगे कि इसकी जांच करवा लें। मैं नानक लेवा संगत पर छोड़ता हूं कि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां कितनी घटिया हरकतें कर रही हैं। लेकिन जब तक जनता मेरे साथ है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है।

'चंपत राय ने पीएम को हिसाब देने से मना किया', केजरीवाल ने उठाए सवाल

(जीएनएस)।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने श्री राम मंदिर जमीन खरीद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के सबूत एसआईटी को सौंप दिए। गुरुवार को एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने संजय सिंह को लखनऊ स्थित कार्यालय में आकर सारे सबूत देने के लिए बुलाया था। संजय सिंह ने जमीन खरीद से संबंधित कुल 11 दस्ताजे सौंपे हैं, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत अन्य कई बड़े नाम इस घोटाले में शामिल हैं।

उधर, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि श्री राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ियों की जांच कर रही एसआईटी को "आप" के सांसद संजय सिंह ने पेश होकर जमीनों के घोटाले के सबूत सौंप दिए हैं।

अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों से कहा कि सोचिए, चंपत राय ने प्रधानमंत्री को हिसाब देने से मना कर दिया। चंपत राय की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? चंपत राय ऐसे क्या राज जानते हैं कि प्रधानमंत्री भी उनके सामने मजबूर हैं? और दूसरी ओर एसआईटी छोटे-छोटे कर्मचारियों को बुला कर सबकी आँखों में धूल झोंक रही है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर से मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे दिल बहुत आहत है। इन लोगों ने भगवान जी का चढ़ावा, उनकी माला और उनकी पादुका तक चोरी कर ली। लोगों ने बहुत भावना के साथ भगवान को जो हीरे-जवाहरात चढ़ाए थे, वे भी चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का कैश और किसी श्रद्धालु द्वारा दी गई 200 किलो चांदी भी चोरी कर ली गई है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे मेरा और मुझ जैसे करोड़ों लोगों का मन बहुत व्यथित है। इसीलिए मैं अभी अयोध्या के लिए निकल रहा हूं। मैं शुक्रवार को राम मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करूंगा। दर्शन करने के बाद हम हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और वहां कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे।

एक सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर किसी के 100 रुपए भी चोरी हो जाएं, तो थाने में उसकी एफआईआर दर्ज होती है। इस मामले में अरबों रुपए चोरी हो गए, कुछ पैसा रिकवर भी हो गया, लेकिन अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मैं तो कानून समझता हूं। मैंने कानून पढ़ा है। बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बन सकती। सीआरपीसी में लिखा है कि एफआईआर के बाद ही एसआईटी बनेगी।

अरविंद केजरीवाल ने एसआईटी पर सवाल उठाते पूछा कहा कि यह एसआईटी किस कानून की किस धारा के तहत बनी है? इसके पास जांच करने की कोई पावर ही नहीं है। यह एसआईटी लोगों की आंखों में केवल धोखा है। यह पूरे मामले में लीपापोती करने के लिए है। इसका काम केवल बड़े-बड़े लोगों को बचाना है। मीडिया में है कि एसआईटी छोटे-छोटे कर्मचारियों को बुलाकर जांच कर रही है, जबकि इतने महीनों और सालों से बड़े स्तर पर चल रही यह चोरी बड़े लोगों की शह के बिना तो नहीं हो सकती।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि चंदे, हीरे-जवाहरात और भगवान की पादुका की चोरी कोई मामूली मामला नहीं है, यह एक बहुत संगीन मामला है जिससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। इस एसआईटी का काम केवल मामले की लीपापोती करना है। इसमें केवल एक नहीं, बल्कि कई सारे मामले हैं, जिनके बारे में शुक्रवार को मैं विस्तार से बताऊंगा।

वहीं, एसआईटी को जमीन खरीद घोटाले के दस्तावेज सौंपने की जानकारी एक्स पर देते हुए संजय सिंह ने कहा कि जमीन खरीद के नाम पर ट्रस्ट ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। मैंने सारे दस्तावेज एसआईटी को सौंप दिए हैं। आगे क्या कार्यवाही होगी प्रभु श्री राम ही जानें? उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के मंदिर में हुए घोटाले से देश के लोगों के मन में काफी आक्रोश और गुस्सा है। चढ़ावे और चंदे की चोरी के कारण करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक एसआईटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। एसआईटी अध्यक्ष ने मुझे बुलाया था और 11 बजे का समय दिया गया था। मैंने मुलाकात करके सारे दस्तावेज एसआईटी अध्यक्ष को सौंप दिए हैं।

संजय सिंह ने बताया कि मेरे पास कुल 13 दस्तावेज थे, लेकिन दो मामले आपस में जुड़े हुए थे। इसलिए मैंने 11 सेट कागज एसआईटी अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य को सौंप दिए हैं। इन दस्तावेजों की जानकारी हैरान करने वाली है। दान की जमीन 1 करोड़ रुपए में खरीदी गई, 9 करोड़ रुपए की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में और 3 करोड़ रुपए की जमीन 24 करोड़ रुपए में खरीदी गई। 3 करोड़ रुपए की जो जमीन 24 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वह नजूल की जमीन है, जिसे न खरीदा जा सकता है और न बेचा जा सकता है। ट्रस्ट ने चंदे का 24 करोड़ रुपए लगाकर उस जमीन को कैसे खरीद लिया?

संजय सिंह ने आगे कहा कि इसके अलावा उस समय के ईडी पार्टी के मेयर के भतीजे दीप नारायण से संबंधित कई कागजात भी मैंने एसआईटी अध्यक्ष को सौंपे हैं, जिसमें बताया गया है कि उसने कैसे चंपत राय को जमीन बेचकर ट्रस्ट को चूना लगाने का काम किया। मैंने वह पुराना खुलासा भी सौंपा जिसमें 2021 में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी और महज 5 मिनट के बाद उसे 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया।

संजय सिंह ने मीडिया को दस्तावेजों का ब्यौरा देते हुए बताया कि 18 मार्च 2021 को कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 4 करोड़ 97 लाख रुपए की जमीन ट्रस्ट ने 8 करोड़ रुपए में खरीदी। इसमें गवाह ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्रा और उस समय के ईडी पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय थे।

दूसरे और तीसरे दस्तावेज में उसी जमीन का जिक्र है जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने 2 करोड़ रुपए में खरीदी और 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दी। इन दोनों खरीद में भी ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा ही गवाह थे।

संजय सिंह ने बताया कि चौथे दस्तावेज के अनुसार 20 फरवरी को 41,60,000 रुपए की जमीन 2 करोड़ रुपए में बेची गई। 5वें और 5-ए दस्तावेज के अनुसार, 21 फरवरी को ईडी पार्टी के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे ने देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी और 7 महीने बाद वही जमीन 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दी।